

## शंभू बॉर्डर पर बैरकिंड्स हटाने की प्रक्रिया

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरकिंड्स हटाने का निर्देश दिया, जहाँ किसान अपनी मांगों के समर्थन में 13 फरवरी, 2024 से डेरा डाले हुए हैं।

### मुख्य बंदि:

- हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला-नई दलिली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरकिंड्स लगा दिये थे।
  - यह **संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक)** और **किसान मजदूर मोर्चा** द्वारा फसलों के लिये **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों का समर्थन करते हुए दलिली तक मार्च करने की योजना की घोषणा के बाद हुआ।
- सुरक्षा बलों द्वारा **उनके मार्च को रोक दिये जाने के बाद** फरवरी से ही किसान पंजाब और हरियाणा के बीच **शंभू तथा खनौरी सीमा पर डटे हुए हैं**।
  - हालाँकि समय के साथ इस स्थल पर किसानों की संख्या में लगातार कमी आई है।



# ₹ न्यूनतम समर्थन मूल्य Minimum Support Price (MSP)

वह दर जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है; किसानों द्वारा वहाँ किये गए उत्पादन लागत के कम-से-कम 1.5 गुणा की गणना के आधार पर

- ❖ सिफारिश:
- ❖ 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' (CACP) द्वारा सरकार को 22 अधिदृष्ट फसलों के लिये 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) तथा गन्ने के लिये 'उचित और लाभकारी मूल्य' (FRP) की सिफारिश की जाती है।
- ❖ 22 अधिदृष्ट फसलें :  
(14 खरीफ, 6 रबी और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें)
- ❖ 7 अनाज- धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी
- ❖ 5 दालें- चना, अरहर/तूर, मूंग, उड़द और मसूर
- ❖ 7 तिलहन- मूंगफली, सफेद सरसों/सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुंभ और रामतिल
- ❖ कच्चा कपास
- ❖ कच्चा जूट
- ❖ नारियल/गरी (कोपरा)

**MSP वह मूल्य है जिस पर सरकार को किसानों से अधिदृष्ट फसलों की खरीद करनी होती है, यदि बाजार मूल्य इससे कम हो जाता है**

- ❖ MSP की सिफारिश में प्रयुक्त कारक:
  - ❖ फसल की खेती में आने वाली लागत
  - ❖ फसल के लिये आपूर्ति एवं मांग की स्थिति
  - ❖ बाजार मूल्य प्रवृत्तियाँ
  - ❖ अंतर-फसल मूल्य समता
  - ❖ उपभोक्ताओं के लिये निहितार्थ (मुद्रास्फीति)
  - ❖ पर्यावरण (मिट्टी तथा पानी के उपयोग)
  - ❖ कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें
  - ❖ MSP की सिफारिश करते समय CACP द्वारा 'A2+FL' और 'C2' दोनों लागतों पर विचार किया जाता है।
  - ❖ MSP का कोई वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है - कोई भी किसान अधिकार के रूप में MSP की मांग नहीं कर सकता है



PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/haryana-to-remove-shambhu-border-barricades>

